June 2026

Uttarakhand Disaster and Accident Analysis Initiative - UDAAI

Social Development for Communities (SDC) Foundation
Dehradun, Uttarakhand
www.sdcuk.in

© 2026 SDC Foundation

SDC Foundation is a Dehradun based environmental action and advocacy group committed to make a positive impact and secure a sustainable future for our home state Uttarakhand, the Himalayas and beyond.

Material from this publication can be used with due acknowledgement.

Editors
Anoop Nautiyal
Prerna Raturi
Gautam Kumar

Research Team
Riya Raj
Misbah Khan
Shubhransh Vir
Praveen Upreti

Contact: SDC Foundation 69, Vasant Vihar,
Dehradun, Uttarakhand (India) - 248001
Website: www.sdcuk.in
Email: contactsdcuk@gmail.com

About UDAAI Monthly Reports

Uttarakhand Disaster and Accident Analysis Initiative (UDAAI) is a monthly initiative by Dehradun-based environmental action and advocacy group, Social Development for Communities (SDC) Foundation. The goal of the UDAAI reports is to document disasters and accidents in Uttarakhand, leading to human and ecological casualties. UDAAI is based on media reports in respectable publications in English and Hindi newspapers, as well as news portals. UDAAI neither attempts nor claims to document all disasters and all accidents in Uttarakhand; its focus instead is to document major casualties and non-casualty events on a regular basis.

We strongly believe that with the perils of inclement climate and unabated disasters, the ecologically fragile and earthquake-prone state of Uttarakhand needs to take many more steps to increase its disaster preparedness. We therefore see UDAAI as a document that highlights attention towards the urgent need for a holistic disaster management and accident minimisation policy framework in Uttarakhand.

It is our earnest hope that UDAAI will spur political leadership, policy makers, bureaucracy, research and academic institutions, businesses, civil society organisations, media and the citizenry at large to initiate inclusive, regular and action-oriented conversations on the subjects of resilience, mitigation and adaptation in Uttarakhand. With mainstreaming and a greater focus on the issue, there is likely to be an improvement in the planning of climate actions and disaster management in Uttarakhand.

Summary of UDAAI Report - June 2026

The UDAAI Report June 2026, highlights some of the most significant environmental and disaster-related issues affecting the Himalayan state. The report emphasizes that climate change, rapid urbanization, increasing tourism, deforestation, and unplanned development are placing unprecedented pressure on Uttarakhand’s fragile ecosystem.It calls for a balanced approach to development that prioritizes environmental sustainability, disaster resilience, and scientific planning.

A major focus of the report is the increasing pressure on the carrying capacity of hill towns and pilgrimage centres, where growing populations, tourism, and infrastructure development are exceeding ecological limits. It stresses the need to implement scientific studies and environmental regulations before approving further development projects. The report also revisits the Karligad disaster, reminding readers that affected communities continue to face challenges in rehabilitation and highlighting the importance of long-term disaster preparedness, resilient infrastructure, and effective recovery planning.

Another key concern is the growing incidence of forest fires across Uttarakhand. The report records the tragic death of a forest guard while fighting a wildfire and notes that forests have been burning for extended periods due to rising temperatures, prolonged dry conditions, and human negligence. These fires threaten biodiversity, increase carbon emissions, and weaken the ecological stability of the region. It recommends strengthening forest management, adopting modern fire detection systems, and encouraging community participation in conservation efforts.

The report further highlights the increasing frequency of extreme weather events, including intense rainfall that caused severe damage in Tharali Bagar, and raises concerns about the reported tilting of the Tungnath Temple, emphasizing the vulnerability of heritage sites in geologically sensitive regions.

Overall, the UDAAI Report concludes that Uttarakhand requires climate-resilient policies, sustainable tourism, scientific land-use planning, and stronger environmental governance to safeguard its people, biodiversity, and unique Himalayan ecosystem while ensuring sustainable development for future generations.

1. June 2, 2026: The carrying capacity of hill towns is increasing and the survey is buried in files.

पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता... बोझ बढ़ता जा रहा और सर्वे फाइलों में दबा

शहरों की धारण क्षमता आकलन की विभागों के पास नहीं है कोई जानकारी

विजेंद्र श्रीवास्तव

देहरादून। प्रदेश के पर्वतीय शहरों पर आबादी, निर्माण और पर्यटन गतिविधियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ये शहर आखिर कितना बोझ सुरक्षित रूप से झेल सकते हैं, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जोशीमठ आपदा के बाद शहरों की धारण क्षमता का वैज्ञानिक और तकनीकी आकलन कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन तीन साल बाद भी यह योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है। स्थिति यह है कि संबंधित विभागों के पास भी इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।

वर्ष 2023 में जोशीमठ आपदा के बाद राज्य सरकार ने सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का सर्वे कराने का निर्णय लिया था। इसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही शहरी विकास, पंचायती राज और अन्य विभागों के सहयोग से यह कार्य किए जाने की बात कही गई थी।

खास खबर

हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी तक इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया है। वहीं, उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (यूएलएमएमसी) ने शहरों की मिट्टी की धारण क्षमता के आकलन की योजना बनाई थी, ताकि भविष्य में विकास योजनाओं और भवन निर्माण को अधिक सुरक्षित एवं वैज्ञानिक आधार पर संचालित किया जा सके। यह योजना भी अब तक प्रारंभ नहीं हो पाई है।

क्या कहते हैं अधिकारी

सचिव आवास आर राजेश कुमार ने बताया कि यह कार्य विभाग के माध्यम से नहीं हुआ है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सर्वे विभाग को कराने की जिम्मेदारी विभाग के पास नहीं थी। यूएलएमएमसी निदेशक शांतनु सरकार ने बताया कि धारण क्षमता का आकलन का कार्य नहीं था, शहरों की मिट्टी की धारण क्षमता के आकलन की योजना है, जिस पर आगे कार्य होना है।

धामों की धारण क्षमता पर मंथन शुरू

देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने धामों की धारण क्षमता पर अपनी प्रारूप रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इस रिपोर्ट पर अब विभिन्न हितधारकों के साथ मंथन शुरू हो गया है। हितधारकों से प्राप्त सुझावों को संकलित कर डब्ल्यूआईआई को भेजा जाएगा, जहां रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2024 में डब्ल्यूआईआई को हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की धारण क्षमता का आकलन करने का काम सौंपा था। डब्ल्यूआईआई ने वहन क्षमता, कूड़ा निकलने और उसके निस्तारण को शामिल किया।

सीवेज के उपचार, वाहन पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था का भी आकलन किया गया। घोड़े-खच्चरों की संख्या और हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी अध्ययन का हिस्सा बनाया गया। डब्ल्यूआईआई ने अपनी प्रारूप रिपोर्ट अप्रैल 2026 में शासन को सौंपी थी। ब्यूरो

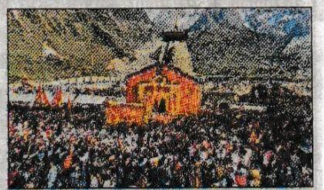

हितधारकों के साथ बैठकें

पीसीबी सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि पर्यटन, बीकेटीसी, पशुपालन विभाग, मंदिर समिति और होटल संघ जैसे सभी हितधारकों को प्रारूप रिपोर्ट भेजी गई है। हितधारकों के साथ बैठकें चमोली और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के माध्यम से भी होनी हैं। ये बैठकें शुरू हो गई हैं और सभी सुझावों का इंतजार है। सभी सुझावों को संकलित कर डब्ल्यूआईआई को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा।

डब्ल्यूआईआई धामों की धारण क्षमता का ड्राफ्ट दिया है। इसके बाद हितधारकों से भी सुझाव लिए जाने हैं। इसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके आधार आगे कदम उठाए जाएंगे। **-आरके सुधांशु,** प्रमुख सचिव वन

AMAR UJALA

JUNE 2, 2026

2. June 2, 2026: Remembering disaster-hit Karligad a year later

पिछले साल 16 जून को कार्लीगाड क्षेत्र में भारी बारिश और फटने की घटनाओं से मची थी भारी तबाही

एक साल बाद आपदाग्रस्त कार्लीगाड़ की याद

i SHOCKING

आपदाग्रस्त क्षेत्र से मलबा हटाने व पुनर्वास कार्यों को 15 दिन का अल्टीमेटम

पिछले साल आई थी आपदा, डीएम ने दिए कड़े निर्देश

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (5 June): सहस्त्रधारा के आपदाग्रस्त कार्लीगाड़ क्षेत्र में राहत कार्यों को लेकर डीएम डॉ. आशीष चौहान ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. जिला प्रशासन ने पूरे प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटाने, नदियों के चैनलाइजेशन और प्रभावितों के पुनर्वास कार्यों को 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. डीएम ने अगले दो हफ्तों निर्धारित डेडलाइन के भीतर कार्य न निपटाने पर सभी विभागों को कार्रवाई के लिए भी चेताया है.

PIC: DAINIK JAGRAN I NEXT

कार्लीगाड में पहाड़ी से आए मलबे को हटाती जेसीबी मशीनें.

मानसून से पहले पूरा हो जाएगा मलबा हटाने का काम

प्रशासन क्षेत्र की निरंतर निगरानी रखे हुए है. प्रत्येक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे प्रभावित परिवारों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके और भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास किया जा सके. बीते रोज डीएम ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ कार्लीगाड़ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर पुनर्वास एवं मलबा हटाने के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. इस दौरान संबंधित विभागों को कार्यों में और अधिक तेजी लाने व निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

DEHRADUN CALLING!

आपदा से ग्रस्त कार्लीगाड क्षेत्र में तबाही के ठीक एक साल बाद मलबा हटाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, शेयर करें अपनी राय.

हमें व्हाट्सएप करें
9411325055

मैनपॉवर बढ़ाने के निर्देश

डीएम डॉ. आशीष चौहान के नेतृत्व में आपदाग्रस्त क्षेत्र कार्लीगाड़, सहस्त्रधारा में युद्धस्तर पर कार्य किए जा रहे हैं. आपदा प्रभावित परिवारों की सुरक्षा व मलबा निष्पादन के उद्देश्य से मशीनरी, मैनपॉवर और अन्य संसाधनों में व्यापक वृद्धि की गई है. आपदा प्रभावित परिवारों की सुरक्षा एवं पुनर्वास कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. सीएम के मार्गदर्शन में सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए राहत, पुनर्वास एवं संरक्षण संबंधी कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

4 पोकलेन व 7 डंपर बढ़ाए

डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि जोखिम वाले क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए, जिससे भविष्य में संभावित आपदाओं के दृष्टिगत जनहानि व संपत्ति के नुकसान की आशंका को कम किया जा सके. आपदाग्रस्त क्षेत्र में मलबा हटाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए खनन विभाग की ओर से 2 अतिरिक्त पोकलेन व जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, जबकि डंपरों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई है. वहीं, सिंचाई विभाग ने नदी के चैनलाइजेशन कार्यों के लिए 2 अतिरिक्त पोकलेन मशीनें लगाई हैं. इससे मलबा निस्तारण व नदी प्रवाह को व्यवस्थित करने के कार्यों में तेजी आई है.

पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के निर्देश

पिछले साल 16 जून को मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण कार्लीगाड में भारी तबाही मची थी. इसके बाद क्षेत्र में मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन बीच में रोक दिया गया. अब मानसून से पहले प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू किया. सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सहस्त्रधारा के आपदाग्रस्त कार्लीगाड़ क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से राहत व पुनर्वास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. डीएम डॉ. आशीष चौहान के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों की सुरक्षा व मलबे के निस्तारण के लिए भारी मात्रा में मशीनरी और मैनपॉवर तैनात की गई है.

1. **संसाधनों में वृद्धि:** मलबे को जल्द से जल्द हटाने के लिए अतिरिक्त मशीनें और श्रमिक तैनात किए गए हैं.
2. **अधिकारियों का निरीक्षण:** डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक के साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर प्रगति की समीक्षा की.
3. **चैनलाइजेशन पर जोर:** मलबे की सफाई के साथ-साथ पानी के सुरक्षित बहाव के लिए नदी-नालों का चैनलाइजेशन किया जा रहा है.
4. **युद्धस्तर पर प्रयास:** तय समय में लक्ष्य हासिल करने के लिए मौके पर तैनात मशीनरी और मैनपॉवर को पूरी क्षमता के साथ झोंक दिया गया है.
5. **प्रशासनिक निगरानी:** डीएम स्वयं इन कार्यों की प्रगति की रोजाना समीक्षा कर रहे हैं, जिससे समयसीमा में कोई चूक न हो.
6. **समयसीमा भी की तय:** सभी संबंधित विभागों को तय समयसीमा के भीतर राहत और पुनर्वास कार्य पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

लगातार मॉनिटरिंग: भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रशासन क्षेत्र पर लगातार नजर रख रहा है.

" आपदाग्रस्त कार्लीगाड में मैनपावर के साथ ही मशीनों की संख्या भी बढ़ाई गई है. अगले 15 दिन के भीतर क्षेत्र में मलबा हटाकर जरूरी लोगों के पुनर्वास के कार्य पूरे करने के निर्देश संबंधित विभागों के अफसरों को दिए गए हैं, जिससे मानसून में बड़े जोखिम को टाला जा सके.

-डा. आशीष चौहान, डीएम

DAINIK JAGRAN INEXT
JUNE 2, 2026

3. June 19, 2026: Forest guard dies in gorge fall after dousing wildfire

Forest guard dies in gorge fall after dousing wildfire

Body Found After Overnight Search By Family, Staff

Ashish Mishra | TNN

Uttarkashi: A forest beat officer died after he allegedly slipped from a hill path and fell into a gorge while returning home after helping douse a forest fire in Thadung beat of Tons forest division in Purola, officials said on Thursday. Sohan Singh Rawat had been sent to control a forest fire in Thadung beat, where he worked with resin-tapping labourers from Resin Coup No 2 to bring the flames under control, on Wednesday evening.

Officials said the fire in compartment number 04 of the beat was contained by evening, after which the workers returned to their camp around 7pm and Rawat also left for home. When Rawat did not reach home till late night, his family started searching for him and informed forest department. A search operation was then launched by forest staff, relatives and villagers. After hours of search, his body was found near Siroda ravine below Kandar.

Officials suspect Rawat slipped on the hilly track while returning after the fire-control operation and fell into the gorge, dying on the spot. Late at night, a forest department team recovered the body and began taking it to sub-district hospital in Purola, but after objections from villagers and family members, it was handed over to his brother Manoj Singh and former village head

Tons deputy conservator of forests D P Baluni visited Rawat's village, met the family and assured them of all possible assistance from the department. Forest officials said Rawat had died in the line of duty and departmental procedures for assistance to the family would be taken up.

BRUTAL BLAZE

571 forest fire incidents char 482 hectares across U'khand

Shivani.Azad@timesofindia.com

Dehradun: Forest fire incidents continue to occur across parts of state's Garhwal and Kumaon regions, with the latest blazes breaking out in the Amri forest beat of Champawat and the Terai Central Forest Division in Nainital district. Forest officials said that some of the alerts received in recent days pertained to non-forest areas as well, while rising temperatures continue to trigger sporadic fire incidents.

According to forest department data, at least 571 forest fire incidents took place during the summer fire season, affecting nearly 482 hectares of forest land. The Garhwal region recorded the highest number of incidents, with 403 fires affecting around 344 hectares of forest area. In Kumaon, 113 incidents damaged nearly 93 hectares, while 55 fires in areas under the wildlife administration affected about 47 hectares.

The Forest Survey of India (FSI) has issued nearly 7,000 forest fire alerts to Uttarakhand since the onset of the fire season in Feb. In the last two days alone -- Wednesday and Thursday -- the FSI sent around 20 fire alerts to the state.

An analysis of forest fire data by the department shows that the maximum area was affected in the Badrinath Forest Division, where about 56 hectares were damaged, followed by the Kedarnath Wildlife Division (41 hectares), Alaknanda Soil Conservation Division (40 hectares) and Pauri Forest Division (40 hectares).

Forest officials said that around 5,600 forest fire watchers and 6,000 departmental personnel are working round the clock to respond to fire incidents as soon as information or alerts are received. Efforts are also underway to activate fire hydrants and implement forest fire management plans across divisions to improve preparedness and response, they added.

TIMES OF INDIA

JUNE 19, 2026

4. June 25, 2026: Forests in the state are burning for 8 months now

चिंताजनक | फायर सीजन खत्म होने के बाद भी नहीं थम रही वनाग्नि, मई-जून में गतवर्ष से चार गुना फैली आग

प्रदेश में अब 8 महीने तक धधक रहे जंगल

■ ओमप्रकाश सती

देहरादून। उत्तराखंड में जंगलों की आग अब वक्त की तय सीमाओं से बाहर निकल चुकी है। राज्य में पारंपरिक फायर सीजन (15 फरवरी-15 जून) समाप्त होने के बाद भी दावानल थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार 15 जून के बाद भी करीब तीन हेक्टेयर जंगल जल चुका है और आग बुझाने के दौरान एक फॉरेस्ट गार्ड की जान भी जा चुकी है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि मई-जून में जंगलों में लगी आग ने पिछले साल के मुकाबले चार गुना ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया है। वर्ष 2025 में इन दो महीनों में जहां 26 हेक्टेयर जंगल जले थे, वहीं इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 280 हेक्टेयर पहुंच गया। इनमें से 275 हेक्टेयर नुकसान सिर्फ मई में हुआ। मंगलवार को भी प्रदेश में 12 स्थानों से फायर अलर्ट मिले, वहीं बुधवार को भी आठ से ज्यादा अलर्ट आए।

मई में जंगल जलने का वर्षवार आंकड़ा

2021-200 हेक्टेयर	2024-260 हेक्टेयर
2022-220 हेक्टेयर	2025-146 हेक्टेयर
2023-270 हेक्टेयर	2026-275 हेक्टेयर

"बदलते मौसम पैटर्न के चलते आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) की ओर से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इन अलर्ट्स का मौके पर सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। **-सुशांत पटनायक,** सीसीएफ वनाग्नि प्रबंधन

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदली तस्वीर के पीछे मौसम का बदलता मिजाज प्रमुख कारण है। प्री-मानसून बारिश सामान्य से कम होने के कारण जंगलों में नमी नहीं बन पाई। वहीं सूखी घास, चीड़ की पत्तियों और तेज गर्म हवाओं ने आग को तेजी से फैलने में मदद की। अब हालात यह हैं कि वनाग्नि की घटनाएं साल के चार महीने नहीं, बल्कि करीब आठ महीने तक देखने को मिल रही हैं। सर्दियों में बारिश की कमी से नवंबर से ही वनाग्नि शुरू हो रही है, जबकि मानसून में देरी के चलते जुलाई के शुरुआती सप्ताह तक आग की घटनाएं जारी रहती हैं।

HINDUSTAN

JUNE 25, 2026

5. April 18, 2026: One hour of rain caused havoc in Tharalibagh

हाईवे-बाजार मलबे से पटे, पेयजल आपूर्ति ठप, कोलूसैंण के जंगलों में हुई अतिवृष्टि के चलते मलबा तेज बहाव के साथ आबादी क्षेत्र तक पहुंचा

थरालीबगड़ में एक घंटे की बारिश ने मचाई तबाही

आपदा की मार

संजय कंडारी

नारायणबगड़। विकासखंड नारायण बगड़ के थरालीबगड़ क्षेत्र में गुरुवार देर रात करीब एक घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी।

कोलूसैंण के जंगलों में हुई अतिवृष्टि के चलते भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर तेज बहाव के साथ आबादी क्षेत्र तक पहुंच गए, जिससे बाजार, सरकारी भवन और राष्ट्रीय राजमार्ग इसकी चपेट में आ गए। लोगों को काफी नुकसान हुआ है। तेज बहाव के दौरान आया मलबा दो हिस्सों में बंट गया। एक धारा अलकनंदा वन प्रभाग के पुराने भवन और राजकीय इंटर कॉलेज के अतिरिक्त कक्षों को क्षतिग्रस्त करती हुई विद्यालय के कार्यालय और परिसर तक पहुंच गई।

वहीं, दूसरी धारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप से गुजरते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंची, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। मलबे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित 12 से अधिक दुकानों में भारी मात्रा में मलबा भर गया। इससे व्यापारियों को नुकसान की आशंका है। वहीं, पार्किंग में खड़े छह से अधिक वाहन भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

नारायणबगड़ के थरालीबगड़ में आपदा के बाद शुक्रवार को जायजा लेते कर्णप्रयाग के नगर पालिकाध्यक्ष गणेश शाह। हिन्दुस्तान

नारायणबगड़ के थरालीबगड़ में गुरुवार रात को भारी बारिश के बाद घर में मलबा और बोल्डर घुसने से हुआ नुकसान। हिन्दुस्तान

पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप: बारिश के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से थरालीबगड़ क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। उपजिलाधिकारी यशवीर सिंह मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया।

कर्णप्रयाग-ग्वालदम-बैजनाथ मार्ग रातभर बंद

मलबा आने से कर्णप्रयाग-ग्वालदम-बैजनाथ हाईवे पूरी रात बंद रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बीआरओ की टीम ने रात से ही युद्धस्तर पर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया और शुक्रवार सुबह लगभग 8:30 बजे यातायात सुचारु कराया जा सका।

1992 से लगातार हो रहा जलभराव, स्थाई समाधान नहीं होने के कारण हालत बदतर

- तेज बहाव के दौरान आया मलबा दो हिस्सों में बंटा
- व्यापारियों को भारी नुकसान
- पार्किंग में खड़े छह से अधिक वाहन भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त

HINDUSTAN
JUNE 27, 2026

6. April 21, 2026: Tungnath temple tilted five degrees

पांच डिग्री झुक गया तुंगनाथ मंदिर

सीबीआरआई को मिली संरक्षण की जिम्मेदारी, 1.77 करोड़ की डीपीआर बनी

राजेश एस. राठौर

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में समुद्रतल से 3680 मीटर (12073 फीट) ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ पर संकट मंडरा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे में मंदिर के पांच से छह डिग्री झुकने की बात सामने आई है। जिससे राज्य सरकार ने मंदिर के संरक्षण के लिए सीबीआरआई को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

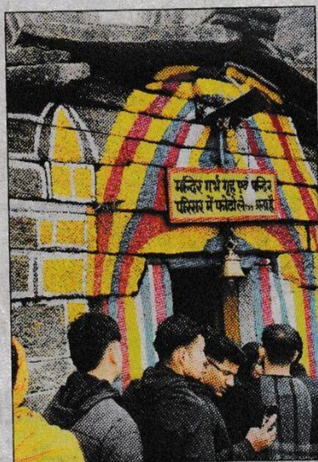

मंदिर की दीवारों पर दरारें स्पष्ट दिखने लगीं। अमर उजाला

मंदिर परिसर की छोटी इमारत लगभग 10 डिग्री झुक गई है। सभामंडप की छत और दीवारों पर दरारें आ गई हैं, जिससे पानी रिस रहा है। जो मंदिर की संरचना और धार्मिक पवित्रता दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। एएसआई नुकसान के कारणों और मरम्मत की आवश्यकता की जांच कर रहा है। अधिकारी जमीन धंसने की संभावना से इन्कार नहीं कर रहे हैं। भू-धंसाव, मौसम बदलाव और भौगोलिक हलचलों को नींव कमजोर होने का मुख्य कारण माना जा रहा है। मंदिर को खतरे में देख

ग्राउंड रिपोर्ट

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा।

इसके बाद तीन संस्थाओं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की ने तुंगनाथ मंदिर और आसपास के इलाके की तकनीकी रूप से जांच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी। इसके बाद पर्यटन और धर्मस्व विभाग ने सीबीआरआई को मरम्मत की जिम्मेदारी दी है।

तुंगनाथ धाम में राज्य निर्माण के 25 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

सुविधाओं का अभाव

मंदिर परिसर में बिजली, पानी, संचार और सफाई व्यवस्था खराब है। यात्राकाल में मंदिर में रहने वाले लोगों को डेढ़ किमी दूर से पानी जुटाना पड़ता है। शीतकाल में मंदिर की सुरक्षा केवल दो सुरक्षा गार्ड के भरोसे रहती है।

2013 की आपदा के बाद से बढ़ गया खतरा

साल 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद से तुंगनाथ धाम में भी खतरा बढ़ गया है। सभामंडप की दीवार के कई पत्थरों ने अपनी जगह छोड़ दी है। ये पत्थर बाहर के लिए खिसक रहे हैं, खाली स्थान को छोटे-छोटे पत्थरों से भरने का प्रयास किया गया है लेकिन वह नाकाफी हैं। तीर्थ पुरोहित रेवाधर मैठाणी ने बताया कि लंबे समय से शासन-प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है। जल्द मंदिर संरक्षण को लेकर ठोस प्रयास नहीं किए गए तो मंदिर की दीवारों के कटवा पत्थर कभी भी भरभरा कर ढह सकते हैं। उन्होंने केदारनाथ धाम की तर्ज पर तुंगनाथ मंदिर की दीवारों की मरम्मत की मांग की है।

धार्मिक मर्यादा भंग होने से तीर्थ पुरोहित चिंतित

हाल ही में पर्यटकों के हुड़दंग की कुछ घटनाएं हुई हैं। यात्रियों में मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं। उपद्रवी पर्यटकों ने स्थानीय खच्चर संचालकों और पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार किया। तुंगनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित इससे चिंतित हैं, उनका कहना है कि तीर्थयात्री अब मंदिरों में पूजा-पाठ के बजाय पिकनिक मना रहे हैं। वे नशे आदि गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इससे धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग हो रही है।

जल्द शुरू होगा पुराने स्वरूप में लाने का काम

बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि तुंगनाथ मंदिर का सीबीआरआई रुड़की ने सर्वे किया है। इसके पुनरोद्धार के लिए 1.77 करोड़ रुपये की डीपीआर बनी है। मंदिर को पुराने स्वरूप में लाने के लिए जल्द काम शुरू किया जाएगा। वहीं, सीबीआरआई वैज्ञानिक डॉ. मनोजित सामंता ने बताया कि सीबीआरआई ने तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सर्वे कर रिपोर्ट सौंप दी है। अब बीकेटीसी को इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी है। जब वह पूरी हो जाएगी सीबीआरआई टीम सभामंडप समेत मंदिर की दीवारों के संरक्षण का कार्य शुरू कर देगी। इसकी योजना तैयार हो चुकी है।

AMAR UJALA

30 JUNE, 2026

About Social Development for Communities (SDC) Foundation

SDC Foundation is a Dehradun-based environmental action and advocacy group engaged in communication, citizen engagement and capacity building in the Himalayan state of Uttarakhand. The foundation works in partnership with institutions of Government of India, Government of Uttarakhand and other stakeholders such as research & academic institutions, community groups, civil society, media partners, NGOs, businesses & trade bodies, schools & colleges in the state.

Climate and environment conservation, waste management, sustainable urbanisation and a basket of sustainable development issues are key focus areas of the foundation.

Anoop Nautiyal,
Founder, SDC Foundation
Dehradun, Uttarakhand
Email: anoop.nautiyal@gmail.com

PS: Errors or omissions in UDAAI documentation, if any, are purely unintentional. In case any errors or key omissions are detected or any fresh updates are available for events that are already documented, SDC Foundation may kindly be notified at the email address contactsdcuk@gmail.com. We shall make the necessary corrections in subsequent versions of the monthly reports of UDAAI.